ने घोषणा की कि पर अवमूल्यन उपाय के रूप में उसने अल्डबरा की योजना खत्म करने का निश्चय किया है।

सरकार ने इस सब पर गौर किया है और स्थिति पर बराबर निगरानी रखी जाती है।

मौरीशस में भारतीय उच्चायोग

8387. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मौरीशस स्थित भारतीय उच्चायोग में कोई सांस्कृतिक सहचारी नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मौरीशस में सांस्कृतिक सहचारी नियुक्त करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : सरकार शीघ्र ही मारिशस में सूचना सहचारी नियुक्त करने का विचार कर रही है जो सांस्कृतिक-कार्य को भी देख रेख करेंगे।

आकाशवाणी से गणतन्त्र दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम का प्रसारण

8388. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गणतन्त्र दिवस से सम्बन्धित इस वर्ष आकाशवाणी के कुल कितने कार्यक्रम प्रसारित किये गये ;

(ख) इन कार्यक्रमों में हिन्दी तथा अंग्रेजी क्रमशः कितने कितने कार्यक्रम थे ;

(ग) 'गणतन्त्र दिवस समापन समारोह' बीटिंग दी रिट्रीट जैसे कार्यक्रम को हिन्दी में प्रसारण न करने के क्या कारण थे ; और

(घ) क्या राष्ट्रीय महत्व के सब कार्यक्रमों का भविष्य में हिन्दी में भी प्रसारण करने का कोई सुझाव विद्यमान है और यदि हां, तो कब तक ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ग) "गणतन्त्र दिवस समापन समारोह" (बीटिंग दी रिट्रीट) पर विशेष न्यूजरील सामान्यतः अंग्रेज़ी में प्रसारित की जाती है। इस कार्यक्रम में सम्मिलित बैंड संगीत कार्यक्रम पश्चिमी संगीत पर आधारित होते हैं। इस कार्यक्रम को दो भाषाओं में एक साथ सारे भारत में प्रसारित करने के लिये वर्तमान ट्रांसमीटर सुविधाएं पर्याप्त नहीं है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम बड़ी संख्या में हिन्दी में अब भी प्रसारित किए जाते हैं। इस प्रकार के अधिकधिक कार्यक्रम हिन्दी में प्रसारित करने का प्रश्न विचाराधीन हैं। ट्रांसमीटर सुविधाओं की कमी होने से कार्यक्रमों को एक साथ दो भाषाओं में सारे भारत में प्रसारित करना फ़िलहाल कठिन है।

Emergency Commissioned Officers

8389. SHRIMATI NIRLEP KAUR : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that those recruited in the army as Emergency Commissioned Officers are being released, whereas those recruited in Navy and Air-Force arer being etained ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) The system of grant of Emergency Commission was introduced only in the Army and *not* in the Air Force and the Navy. As such, the question of release of Emergency Commissioned Officers in the Air Force and the Navy does not arise. It has been decided that

the E.C.Os. in the Army who are suitable and willing to be considered for the grant of Permanent Commission will be granted P.C. to the extent vacancies are available for them, if found fit after screening.

(b) The reasons for the release in a phased programme after 1967 to 1970 of the Emergency Commissioned Officers who do not nake the grade for the grant of P.C. are :—

(i) Emergency Commissioned Officers were granted such commission, based on the relaxed standards for selection in order to meet the requirement of the Army at that time.

(ii) Some of these officers are not eligible for Permanent Commission on account of higher age or low medical category.

(iii) The grant of Permanent Commission to all these officers would not only affect the efficiency of the army but would also create an imbalance in the service structure of the officers' cadre.

(iv) Some of them, though eligible, were not willing to apply for Permanent Commission.

Strike in B.E.L., H.A.L. and Bharat Earth Movers Ltd.

8390. SHRI K. LAKKAPPA :
SHRI GEORGE FERNANDES:
SHRI S. R. DAMANI :
SHRI K. P. SINGH DEO :
SHRI M. L. SONDHI :
SHRI K. M. KOUSHIK :
SHRI MEETHA LAL MEENA :
SHRI S. M. BANERJEE :
SHRI RAJA RAM :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of Bharat Electronics Ltd., Hindustan Aeronautics Ltd. and Bharat Earth Movers' Ltd. are on strike ;

(b) if so, what are their demands ;

(c) the steps taken by Government to settle the dispute ; and

(d) the extent of set-back to production ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE PRODUCTION (SHRI L. N. MISHRA) : (a) No, Sir. In the Bangalore Division of the Hindustan Aeronautics Ltd. and the Rail Coach Division of the Bharat Earth Movers Ltd. there was a tool-down strike from 25th March to 3rd April 1968 when the managements had to declare a lock-out. As a result of the negotiations, a settlement was reached and these units have started working with effect from 15th April 1968.

(b) and (c). Do not arise.

(d) Approximately Rs. 100 lakhs.

पाकिस्तान द्वारा युद्ध-विराम का उल्लंघन

8391. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री ने हाल में राज्य विधान सभा में कहा था कि पाकिस्तान ने ताशकन्द समझौता होने के बाद 22 अवसरों पर युद्ध-विराम रेखा का उल्लंघन किया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि सीमा उल्लंघन की उक्त घटनाओं में 6 व्यक्ति मारे गये, 4 व्यक्ति घायल हुए और 6 व्यक्तियों का अपहरण हुआ इनके परिणाम स्वरूप भारत को कुछ और हानि उठानी पड़ी ; और

(ग) यदि उपयुक्त भाग (क) और (ख) को उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इन घटनाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और उस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) से (ग) : सरकार का ध्यान जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मन्त्री के रिपोर्ट किए गए वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है । यह सच है कि पाकिस्तान द्वारा किए गए युद्धविराम अतिक्रमण कभी-कभी युद्ध विराम रेखा के अपनी तरफ हताहत और क्षति में परिणत हुए है । संयुक्त राष्ट्रों के सैनिक प्रेक्षकों को युद्ध विराम उल्लंघन